



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 1, 1982 (वैशाख 11, 1904)
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1, 1982 (VAISAKHA 11, 1904)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये संकल्पों और असांख्यिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएँ	387
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएँ	587
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये संकल्पों और असांख्यिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएँ	9
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएँ	587
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के जिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरण (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये सामान्य सांख्यिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियाँ आदि भी शामिल हैं)	743
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरण संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांख्यिक आदेश और अधिसूचनाएँ	1483
भाग II—खण्ड 3(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांख्यिक नियमों और सांख्यिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप भी उपविधियाँ भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	177
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांख्यिक नियम और आदेश	91
भाग III—खण्ड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ	5743
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ और नोटिस	225
भाग III—खण्ड 3—मुख्य प्रायुक्तों के प्राधिकार के अधीन भयबा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ	107
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएँ जिनमें सांख्यिक निष्कायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1703
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	117
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	387	PART II—SECTION 3(iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	177
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	587	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	91
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..	9	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	574 3
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	587	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	225
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	107
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1703
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	117
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	743	PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1483		

भाग I—खण्ड 1 PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नियम

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 1982

सं० 9/1/82-के०से०-11 अगस्त, 82 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग तथा भारत निर्वाचित आयोग के सचिवालय के उच्च श्रेणी ग्रेड की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए निम्न सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

2. चयन सूचियों में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित ढंग में किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस तमोर् भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) मध्य राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (मध्य राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संविधान) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किए गए, के अनुसार संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति, आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967, संविधान (गावा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गावा, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (मणिपुर) अधिनियम 1976, संविधान (मिज़ोरम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग अथवा भारत के निर्वाचित आयोग

के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो 1 अगस्त, 1982 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा :—

(1) सेवा की अवधि

1 अगस्त, 1982 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में अथवा पर्यटन विभाग के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा अथवा भारत के निर्वाचित आयोग के सचिवालय में उसकी 3 वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित हुए होते चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए।

परन्तु यदि भारत के निर्वाचित आयोग के सचिवालय के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा भी शामिल है, के परिणामों के आधार पर हुई हो, तो एम।परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले घोषित हुए होते चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए।

टिप्पणी :— 1. स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा पर्यटन विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी :— 2. अनुमोदित तथा लगातार सेवा की 3 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी, यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः भारत के निर्वाचित आयोग के सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी :— 3. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचित आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसमें 26 अक्टूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्टूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से

प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेवा में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा; अथवा

टिप्पणी 4:— ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सभ्य प्राधिकारी की अनुमति से निःसर्गगीय पदों पर प्रतिनियुक्त हों उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा तथा वह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में निःसर्गगीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेगुलेरी बॉडी सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचित आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण-अधिकार (लियन) न रखते हों।

(2) आयु. —

(क) यदि वह पैरा 1 में वर्णित किन्हीं भी संस्थाओं में स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक है तो 1-8-82 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1932 से पूर्व नहीं हुआ हो।

(ख) उपरिलिखित ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी —

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्ला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रवेश किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्ला देश) का सदभावित विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रवेश किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सदभावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रवेश किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सदभावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्टूबर 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रवेश किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य में प्रवेश किया हो या जर्जिया, मलावी, जेरे और इथोपिया में प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तथा केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) जो जर्जिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से प्रवाप्त हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रवेशित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रवेशित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(x) किसी दूसरे देश में संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कर्मियों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश में संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कर्मियों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक;

(xii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक;

(xiii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कर्मियों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों;

(xiv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया है, तो उसके मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक;

(xv) यदि उम्मीदवार वियतनाम में भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया हो और वह किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तो उसके मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक और

(xvi) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो तो अधिक से अधिक 10 वर्ष।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जायेगी।

(3) टंकण परीक्षा :—यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण-शाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कूल)/अधीनस्थ सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग को मासिक/तिमाही टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।

5 परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हों।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए बोरी कोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने—

- (i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
- (ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
- (iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा
- (iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा
- (v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
- (vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
- (vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा
- (viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा
- (ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अव्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—
- (क) आयोग द्वारा इस परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, के लिए, अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा
- (ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—
- (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से, वारित किया जा सकता है, और
- (ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जायेगा।

9. उन उम्मीदवारों को छोड़ कर जो इस आयोग की विज्ञप्ति के उपबन्धों के अनुसार फीस माफी का दावा करने हों, बाकी उम्मीदवारों को निम्नलिखित फीस का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

10. आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की चार अलग-अलग सूचियाँ तैयार करेगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गये हों।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सकें, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किए बिना, यदि वे योग्य हों तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकती है।

टिप्पणी :— उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जायें, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार

के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया ही जाये।

11. हर उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से ही चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जाच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है।

किन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिए सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय मन्त्रिालय लिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड मन्त्रिालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग के अपने पद से त्यागपत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निरन्वर्गीय पद या दूसरी सेवा में “स्थानान्तरण” द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और के० म० लि० से०/रेलवे बोर्ड मन्त्रिालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उस अवसर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निरन्वर्गीय पद पर प्रतिनियुक्त किया जा चुका हो।

एच० जी० मंडल, अवर सचिव

परिणित

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग 1. नीचे परिच्छेद 2 में बताया गए विषयों की कुल 300 अंकों को लिखित परीक्षा।

भाग 2. आयोग द्वारा विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवावृत्तों (रिक्त और सचिव) का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा में ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं, जिनके बारे में आयोग फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे।

2 भाग 1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा :—

विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय
(1) निबन्ध तथा सार लेखन		
(क) निबन्ध 50	100	2 घण्टे
(ख) सार लेखन 50		
(2) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पत्र	100	2 घण्टे
(3) सामान्य ज्ञान	100	2 घण्टे

टिप्पणी :—तीन श्रेणियों अर्थात् :— (i) के० म० लि० सेवा तथा पर्यटन विभाग

(ii) रेलवे बोर्ड म० लि० सेवा

(iii) निर्वाचन आयोग

के उम्मीदवारों के लिए टिप्पण, प्रावण तथा कार्यालय पत्रों के प्रश्न-पत्र अलग-अलग होंगे।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी, या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न-पत्रों अथवा (i) निबन्ध या सारलेखन, अथवा (ii) टिप्पणी लेखन/मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति अथवा (iii) सामान्य ज्ञान में से किसी एक प्रश्न-पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है।

टिप्पणी-1-- यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न-पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए।

टिप्पणी-2-- जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते ह उन्हें यह बात आवेदन-पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप में लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी-3-- एक बार रखा गया विकल्प अनिवार्य माना जायेगा और आवेदन-पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने से सम्बन्धित अनुरोध साधारणतः स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-4-- प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए जायेंगे।

टिप्पणी-5-- उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई (आप्ट की गई) भाषा को छोड़ कर अन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आवेदन अपने विषय में परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्थक अंक (क्वालीफिकेशन नम्बर) निर्धारित कर सकते हैं।

7. केवल कोरे सही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिए जायेंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भाषाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग में और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

(1) निबन्ध तथा सार लेखन

(क) निबन्ध--विहित कई विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा।

(ख) सार लेखन--सूक्ष्म सार लिखने के लिए सामान्यतः अनुच्छेद दिए जायेंगे।

(2) टिप्पणी व आलेख तथा कार्यालय पद्धति--इस प्रश्न-पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों को योग्यता ज्ञापना है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों का चाहिए कि इसके लिए कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तक (मैन्युअल आफ ऑफिस प्रोसीजर)--सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियाँ ब्लू आफ प्रोसीजर एण्ड कण्ट्रबुट्स आफ विजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा तथा पर्यटन विभाग के उम्मीदवारों को चाहिए कि वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति सहित और लोक सभा और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा वायसचालन के नियमों और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की हस्त-पुस्तिका और इस प्रयोजन के लिए राज भाषा के प्रयोग से सम्बन्धित भारतीय रेलवे के आदेशों के मकलन का अध्ययन करें।

भारत के निर्वाचित आयोग के उम्मीदवारों का चाहिए कि वे कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तक (मैन्युअल आफ ऑफिस प्रोसीजर)--सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियाँ, तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग से सम्बद्ध गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

(2) सामान्य ज्ञान--सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशों का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों की वर्तमान घटनाओं के प्रति बुद्धिमतापूर्ण जागरूकता (जसकी किसी निर्दिष्ट मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है) का परीक्षा लेना है। प्रत्याशियों के उत्तरों में उनके लिए किसी पाठ्य पुस्तकी, प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की अपेक्षा नहीं अपितु उनके प्रश्नों को बुद्धिमतापूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित होनी चाहिए।

नागरिक प्रति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 1982

संकल्प

ग० ई० 11011/23/80 हिन्दी--नागरिक प्रति मंत्रालय के 3 अगस्त, 1981 तथा 4 नवम्बर, 1981 के संकल्पों के क्रम में भारत सरकार निम्नलिखित को 3-8-81 के संकल्प के क्रमांक (3), (5) और (6) के अन्तगत नागरिक प्रति मंत्रालय की हिन्दी महाहकार समिति का सदस्य नामित करती है--

लोक सभा सदस्य

(3) श्री दया राम शास्त्री (समद सदस्य) सदस्य

राज्य सभा सदस्य

(5) श्री जे०के० जैन (समद सदस्य) सदस्य

(6) श्री मुणील चन्द्र मोहन्ता (समद सदस्य) सदस्य

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त संकल्प की क्रम सं० 11 के सामने से श्री मुणील चन्द्र वर्मा का नाम हटा दिया जाए और क्रम संख्या 11 को निम्न प्रकार पढ़ा जाए--

(1) अध्यक्ष,
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी पारंपद्,
नई दिल्ली।

आवेश

आवेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमन्त्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

टी० आर० परमेश्वरम्, संयुक्त सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1982

संकल्प

सं० ई०-11011(15)-५० हिन्दी — ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के तारीख 21 जुलाई 1981 के इसी संस्था के संकल्प में आर्थिक वर्षाघन करने हुए, भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्त को ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिन्दी मलाहकार समिति की मदद से से हटाने का निर्णय किया है :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग,
3-इला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
बम्बई-400056

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों/सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासकों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए, संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अतुल सिन्हा, उप सचिव

मिजोई मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1982

संकल्प

सं० 2(2)/80-बा०-नि०-—ब्रह्मपुत्र बाढ़-नियंत्रण बोर्ड के, जिसका गठन ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़-नियंत्रण की समस्याओं पर कानूनी पाने के लिए, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मई, 1970 के संकल्प सं०

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS)

New Delhi, the 1st May 1982

RULES

No. 9/1/82-CS.II.—The Rules for a Limited Departmental Competitive Examination for inclusion in the Select Lists for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service, Department of Tourism and Secretariat of Election Commission of India to be held by the Staff Selection Commission in August, 1982 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select Lists will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government. Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Schedule Castes Order, 1962, the Constitution

वि० का०-पांच-502(37)/68 द्वारा किया गया था, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना को देखते हुए, जिसका गठन इस मंत्रालय की दिनांक 28-12-1981 की अधिसूचना सं० सा० प्रा० सं० 926(ई०) द्वारा किया गया था, 31-12-1981 में पत्रद्वारा विघटित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राज्य सरकार/भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/प्रधान मंत्री सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव/भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/योजना आयोग की सूचनाएं भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और राज्य सरकार से, इसे आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाए।

एग० के० अग्रवाल, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 1982

सं० क्र०-16012/3/82 डब्ल्यू० ई० (एन० एल० आई०) — राष्ट्रीय श्रम संस्थान के, जी मोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत पंजीकृत मोसाइटी है, नियम और विनियम के नियम IX (i) (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उप श्रम मंत्री को डा० डी० टी० लाकड़वाला के स्थान पर इस संस्थान की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

आर० के० ए० सुब्रह्मण्य, अपर सचिव

(Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service, or the Department of Tourism, or the Election Commission of India who on the 1st August, 1982 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination.

(1) Length of Service

He should have on the 1st August, 1982 rendered an approved and continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service or in the post of Lower Division Clerk in the Department of Tourism or an approved and continuous service of not less than 3 years in the post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service,

Railway Board Secretariat Clerical Service, or the Department of Tourism on the results of a competitive examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 5 years before the crucial date and he should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that Grade.

Provided that if he had been appointed to a post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India on the results of a Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 3 years before the crucial date and he should have rendered not less than 2 years approved and continuous service in that Grade.

NOTE 1 : The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Department of Tourism.

NOTE 2 : The limit of 3 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

NOTE 3 : Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or of the Secretariat of Election Commission of India or of Department of Tourism who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency, issued on 26th October, 1962, namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

NOTE 4 : Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This, however, does not apply to a Lower Division Clerk, who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Secretariat of Election Commission of India or Department of Tourism.

(2) Age—

(a) He should not be more than 50 years of age on 1-8-1982 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1932, if he is a permanent or regularly appointed Lower Division Clerk of any of the services mentioned in para 1 above.

(b) The upper age limit prescribed above will be further relaxable—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiv) upto a maximum of three years if the candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July, 1975;

(xv) upto a maximum of eight years if the candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975; and

(xvi) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

(2) Typewriting Test : Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing)/Subordinate Service Commission/Staff Selection Commission

for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of the examination

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

- (i) obtaining support for his candidature by any means or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means in the examination hall, or
- (viii) misbehaving in the examination hall, or
- (ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

- (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or
- (b) to be debarred either permanently or for a specified period;
 - (i) by the Commission from any examination or Selection held by them;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them, and
- (c) to disciplinary action under the appropriate rules

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any mean, may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the prescribed fee except those who are claiming fee concession in terms of provisions in the Commission's notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in four separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade upto the required number :

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection;

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Administrative Reforms.

13. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by the Department or, who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism will not be eligible for appointment on the results of the examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

H. G. MANDAL, Under Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination, a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subjects	Maximum Marks	Time allowed
(1)	(2)	(3)
(i) Essay and Precis Writing :		
(a) Essay	50	
(b) Precis-Writing	50	100 2 hours.
(ii) Noting and Drafting and Office Procedure	100	2 hours
(iii) General Knowledge	100	2 hours

NOTE : There will be separate papers on Noting, Drafting and Office Procedure for candidates belonging to the three categories, viz. (i) C.S.C.S. and Department of Tourism, (ii) R.B.S.C.S. and (iii) Election Commission.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz. (i) Essay and Precis writing or (ii) Noting and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

NOTE 1 :—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2 :—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3 :—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in Column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

NOTE 4 :—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

NOTE 5 :—No credit will be given for answer written in a language other than the one opted by the candidate.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

1. Essay and Precise Writing :

(a) Essay—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) Precise Writing—Passages will usually be set for summary or precise.

2. Noting and Drafting and Office Procedure—The paper on Noting and Drafting and office Procedure will be designed to test the candidates knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts.

Candidates belonging to Central Secretariat Clerical Service or Department of Tourism are required to study the Manual of Office Procedure Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management—the Rules of Procedure and Conduct or Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purposes of the Union for this purpose.

Candidates belonging to Railway Board Secretariat Clerical Service are required to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board and the Rules of Procedure and Conduct or Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for official purposes of the Union and the Indian Railways Compendium of Orders regarding use of Official Language for this purpose.

Candidates belonging to Election Commission of India are required to study the Manual of Office Procedure, Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purpose of the Union for this purpose.

3. General knowledge—The paper on General knowledge will be intended INTER ALIA to test the candidate's knowledge of Indian Geography as well as the country's administration, as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 8th April 1982

RESOLUTION

No. E.11011/23/80-Hindi.—In continuation of Ministry of Civil Supplies Resolutions of even number dated the 3rd August, 1981 and 4th November, 1981, the Government of India hereby nominate the following as a member of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Civil Supplies

against S. No. 3, 5 and 6 of the Resolution dated 3-8-81 :—

Member of Lok Sabha

(3) Shri Daya Ram Shakya Member
(Member of Parliament)

Member of Rajya Sabha

(5) Shri J. K. Jain Member
(Member of Parliament)

(6) Shri Sushil Chand Mohunta Member
(Member of Parliament)

In addition the name of Shri Sushil Chandra Varma, given against S. No. 11 may be deleted and S. No. 11 may be read as follows :—

11. President,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,
New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. R. PARMESHWARAN, Jr. Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 31st March 1982

RESOLUTION

No. E.11011/15/80-Hindi.—In partial modification of Ministry of Rural Reconstruction's Resolution of even number dated the 21st July, 1981, the Government of India have decided to delete the name of the following person as member of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Rural Development.

Chief Executive Officer,
Khadi and Village Industries Commission,
3, Irla Road, Ville Parle (West),
Bombay-40056.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ATUL SINHA, Dy. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 26th March 1982

RESOLUTION

No. 2(2)/80-FC.—Brahmaputra Flood Control Board which was constituted by the Government of India vide Resolution No. DW. V. 502(37)/68 dated the 13th May, 1970, to tackle the flood control problems of the Brahmaputra Valley, is hereby dissolved in view of the establishment of the Brahmaputra Board with effect from 31-12-1981 constituted vide this Ministry's Notification S. O. No. 926 (E) dated 28-12-1981.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Government/All Ministries of Government of India/Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India/Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government be requested to publish it in the State Gazette for general information.

S. K. AGGARWALA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 12th April 1982

No. Q-16012/3/82-WF (NLI).—In pursuance of Rule IX (i) (a) of the Rules and Regulations of National Labour Institute a Society registered under the Societies Registration Act, 1860, (Punjab Amendment) Act, 1957 the Central Government hereby appoints the Deputy Labour Minister as the Chairman of the Executive Council of the Institute vice Dr. D.T. Lakdawala.

R. K. A. SUBRAMANYA, Addl. Secy.

